राज्यपाल सचिवालय, बिहार
राजभवन, पटना–800022

प्रेस–विज्ञप्ति

राजभवन में कुलाधिपति की अध्यक्षता में समीक्षा–बैठक सम्पन्न

पटना, 18 दिसम्बर 2017

आज राजभवन के सभागार में महामहिम राज्यपाल–सह–कुलाधिपति श्री सत्य पाल मलिक की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयों के क्रिया–कलापों की समीक्षा के लिए प्रथम मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी पारम्परिक विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री आर॰के॰ महाजन, राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग श्री राहुल सिंह, अपर सचिव, शिक्षा विभाग श्री मनोज कुमार सहित कुलाधिपति कार्यालय के सभी वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

बैठक में विगत 25 नवम्बर को राजभवन में सम्पन्न कुलपतियों की बैठक में लिए गये सभी प्रमुख निर्णयों की बारी–बारी से विश्वविद्यालय–वार समीक्षा हुई।

1. बैठक के दौरान राज्य सरकार के 'सात निश्चय' के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 'वाई फाई' संस्थापित करने की योजना के कार्यान्वयन की गंभीरता से समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि राज्य में 290 विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय परिसरों में वाई–फाई सुविधा संस्थापित कर दी गई है। किन्तु, साथ ही यह स्पष्ट हुआ कि विद्युत–आपूर्ति की असुविधा, नोडल आफिसर द्वारा ऑनरशिप ग्रहण नहीं करने आदि कारणों से Users Enrollment में काफी कमी है। बैठक के दौरान यह निदेशित किया गया कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के नोडल ऑफिसर तथा वाई–फाई सेवा उपलब्ध करानेवाली एजेन्सी के संबंधित पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह के एक निश्चित दिन बैठक कर स्थिति की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि यूजरों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो, अधिकाधिक यूजरों को यूजर्स नेम एण्ड पासवर्ड अविलम्ब उपलब्ध करा दिए जाएँ तथा इसके लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के सूचना–पट पर 'आवश्यक सूचना' भी प्रकाशित कर दी जाय। कुलपतियों को 'वाई–फाई' की यह सुविधा प्रथम चरण में सभी विश्वविद्यालय मुख्यालयों एवं स्नातकोत्तर विभागों तथा बाद में सभी महाविद्यालयों में शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया।

2. बैठक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय भवनों में छात्राओं के लिए 'वाशरूम' निर्माण की योजना की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि सभी विश्वविद्यालय इस योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्पर हैं। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हर हालत में इस योजना का कार्यान्वयन मार्च 2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

लगातार.....पृष्ठ...2 पर

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय आवश्यकतानुसार अपेक्षित प्राक्कलन सहित राशि उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र शिक्षा विभाग से अनुरोध करेंगे। यह भी निर्णय हुआ कि जरूरत के मुताबिक, सहयोग के लिए सुलभ इंटरनेशलन से भी सम्पर्क किया जाएगा।

3. बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि दिसम्बर के अंतिम सप्ताह से लेकर आगामी जनवरी के शुरूआती सप्ताह तक में प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय अपने परिसर में 'विशेष स्वच्छता अभियान' संचालित करेंगे, जिसमें एन॰सी॰सी॰/एन॰एस॰एस॰ के विद्यार्थियों के साथ–साथ सभी शिक्षक एवं विद्यार्थी शामिल होंगे। इस विशेष स्वच्छता अभियान का अनुपालन प्रतिवेदन 5 जनवरी, 2018 तक भेजने को कहा गया, साथ ही इस अभियान को प्रत्येक महीने दुहराने का भी निर्णय हुआ।

4. पटना, मगध, ललित नारायण मिथिला एवं बी॰आर॰ए॰ बिहार विश्वविद्यालयों को अपने वास्तविक बजट प्राक्कलन अविलम्ब शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि सेवान्त लाभ के मामलों में भुगतान में असुविधा नहीं हो।

5. छात्र–संघ चुनाव शीघ्र कराने हेतु कुछ कुलपतियों से प्राप्त सुझावों पर शीघ्र विचार करते हुए निर्णय लिये जाने पर सहमति बनी।

6. विश्वविद्यालयों में बायो–मेट्रिक पद्धति के जरिये उपस्थिति सुनिश्चित कराने की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि अधिकतर विश्वविद्यालयों में योजना का कार्यान्वयन तेजी से शुरू हो गया है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं सभी स्नातकोत्तर विभागों में मार्च 2018 तक तथा सभी महाविद्यालयों में जून 2018 तक बायो–मेट्रिक के जरिये उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करा दी जाएगी।

7. बैठक में विश्वविद्यालय स्तर पर Grivances Redressal Cell को प्रभावी एवं मजबूत बनाने का निर्णय लिया गया, ताकि छात्रों एवं शिक्षकों के विभिन्न मामलों का ससमय समुचित निष्पादन हो सके।

8. बैठक में सम्बद्ध महाविद्यालयों (Affliated Colleges) में शिक्षकों/कर्मियों के वेतन–भुगतान आर॰टी॰जी॰एस॰ पद्धति से बैंक–खातों के माध्यम से कराने पर गंभीरतापूर्वक विचार का निर्णय लिया गया। साथ ही इनके पी॰एफ॰/ई॰पी॰एफ॰ कटौती को भी अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया गया।

9. बैठक में विश्वविद्यालयों में राशि दान कर सीनेट का आजीवन सदस्य बनने के लिए निर्धारित राशि 25 हजार को बढ़ाकर 25 लाख करने पर भी गंभीरतापूर्वक विचार का निर्णय लिया गया। सीनेट/सिन्डिकेट में चुनाव के जरिये निर्वाचित होनेवाले विभिन्न प्रतिनिधियों के चुनाव हेतु भी कैलेण्डर तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया।

लगातार....पृष्ठ...3 पर

10. इस उच्चस्तरीय बैठक में 'एकेडमिक कैलेण्डर' को मार्च 2018 तक तैयार कर प्रस्तुत कर देने का भी निर्णय लिया गया एवं विलम्बित परीक्षाओं को शीघ्र संचालित कर हर हालत में सत्र को अगले वर्ष से नियमित (Regular) कर देने का निर्णय लिया गया।

11. विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम (Curriculum) अत्यधिक पुराने हो गये हैं। अतः Choice Based Credit System के आधार पर नया पाठ्यक्रम तैयार करने का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए पटना विश्वविद्यालय के कुलपति को सक्षम एवं अनुभवी अध्यापकों को प्रतिनियुक्त करने के लिए कहा गया जो यू॰जी॰सी॰ तथा अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए नया पाठ्यक्रम तैयार करने में सहयोग करेंगे। नया पाठ्यक्रम शीघ्र बनाकर चरणबद्ध तरीके से अन्य सभी विश्वविद्यालयों में भी लागू किया जायेगा। पाठ्यक्रम–निर्धारण में यह प्रयास होगा कि शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया जा सके।

बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री मलिक ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और चरणबद्ध रूप से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को बैठकों में लिए गए निर्णयों का शत् प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चत करना चाहिए, ताकि राज्य में उच्च शिक्षा का समग्र विकास हो सके।

.....